देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 25.02.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- हरिद्वार में कुम्भ मेला–2027 के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए मेला प्रशासन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत कार्यों को आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए।
- चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में। सुरक्षा प्रतिबंधों और मानकों का रखा जा रहा विशेष ध्यान
- खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल व युवा कल्याण विभाग में करीब 544 पदों को सृजित करने के लिए शासन को पत्र लिखा।
- सतत विकास लक्ष्य, पीएम गति शक्ति और विजन–2047 पर अल्मोड़ा में कार्यशाला का आयोजन।

<u>कुंभ मेला</u>

हरिद्वार में अगले साल कुम्भ मेले के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए मेला प्रशासन द्वारा स्थायी विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, सुगमता और स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। मेला प्रशासन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत कार्यों को आगामी 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं, मेलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नामित अधिकारी लगातार कार्यस्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि निर्माण कार्यों की प्रगति गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके। मेला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी कड़ी में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कुम्भ मेला के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण सामग्री की नियमित जांच कराने और सभी तकनीकी व गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक कार्य की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मेला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा।

<u>चारधाम हेली सेवा</u>

प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में है। इस बार पूरी प्रक्रिया नागर विमानन महानिदेशालय– डीजीसीए के सुरक्षा प्रतिबंधों और मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरी की जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान उड़ान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ और बदरीनाथ में नए हवाई यातायात नियंत्रण सेवा स्थापित करने, लाइव ट्रैकिंग

डिवाइस लगाने, ग्राउंड हैंडलिंग को सुदृढ़ करने और मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

<u>मुख्य सचिव बैठक</u>

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना– रीप की उच्चाधिकार व मार्गदर्शन समिति की बैठक हुई। बैठक में सचिव डी.एस. गर्ब्याल ने वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति व अनुपालन रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना व बजट का प्रस्तुतीकरण किया। समिति ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लगभग 677 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना और बजट को अनुमोदित किया। प्रस्तावित कार्ययोजना में स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यक्रमों को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने वर्ष 2026–27 के लिए ढाई लाख लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने निर्देशित किया रीप परियोजना से लाभान्वित महिलाओं को अन्य विभागीय और केंद्र व राज्य योजनाओं से भी जोड़ा जाए तथा सभी योजनाओं का समेकित विवरण संकलित किया जाए। मुख्य सचिव ने समान कार्य प्रकृति वाले महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें आजीविका व स्वरोजगार की दृष्टि से बेहतर सहयोग देने की रणनीति तैयार करने की बात भी कही।

खेल मंत्री

खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में खेल व युवा कल्याण विभाग में करीब 544 पदों को सृजित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने विभाग में लंबे समय से चली आ रही रिक्तियों को भरने की वकालत की है। श्रीमती आर्या ने कहा कि बार–बार शासन से अतिरिक्त पदों की मांग करने में काफी समय लग जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक साथ 544 पदों की मांग रखी है। पत्र में 244 पद विशेष रूप से प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है।

<u>कार्यशाला</u>

अल्मोड़ा जिले के मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सतत विकास लक्ष्य, पीएम गति शक्ति और विजन–2047 विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने सतत विकास लक्ष्यों के 17 वैश्विक लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। जिला स्तर पर इन लक्ष्यों की प्रगति की नियमित निगरानी और डेटा अपडेट करने पर विशेष बल दिया गया। वहीं, पीएम गति शक्ति के तहत मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना विकास और परियोजनाओं के समयबद्ध

व समन्वित क्रियान्वयन की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अधिकारियों को योजनाओं के प्रस्ताव और प्रगति विवरण को पोर्टल पर अद्यतन रखने तथा विभागीय समन्वय से परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए निर्देशित किया गया। कार्यशाला में विजन–2047 के संदर्भ में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु स्थानीय स्तर पर ठोस रणनीति बनाने, जनसहभागिता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई।

होली/पुलिस अलर्ट

देहरादून में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून–व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि होली के त्यौहार को लेकर सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है।

एमडीडीए

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण– एमडीडीए की ओर से अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन को सील किया। प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। श्री तिवारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद भी कार्य नहीं रुकने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें।